इस्माइल सैबारी को डच क्लब पीएसवी से 542 करोड़ रुपये में साइन किया
Page-04

tv भारतवर्ष
सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

किश्वर मर्चेंट का बीच पर किलर लुक
Page-05

भारत-जापान के रिश्तों को नई मजबूती
अहम समझौतों पर मुहर

जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के भारत दौरे के दौरान नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिष्टमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने भारत-जापान संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच वर्षों से बना आपसी विश्वास पहले से अधिक मजबूत हुआ है और यही भरोसा भारत-जापान रणनीतिक साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उन्हें अपनी "छोटी बहन" भी बताया।वार्ता के दौरान दोनों देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), रक्षा, ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। सबसे अहम समझौतों में एआई क्षेत्र में साझेदारी शामिल रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान की अत्याधुनिक तकनीक और भारत की मजबूत सॉफ्टवेयर क्षमता का समन्वय वैश्विक स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को नई दिशा देगा। दोनों देशों ने एआई अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास में मिलकर काम करने का निर्णय लिया।बैठक के दौरान जापान ने भारत में लगभग 10 अरब डॉलर के नए निवेश की घोषणा की। यह निवेश आधारभूत ढांचे, विनिर्माण, उच्च तकनीक और औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। इसके साथ ही हाइड्रोजन ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा और न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। पहली बार भारत और जापान रक्षा प्रौद्योगिकी के संयुक्त विकास पर साथ काम करेंगे। इसके तहत नौसेना के लिए 'यूनिकॉर्न' रेडियो एंटीना विकसित करने की परियोजना शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि इससे समुद्री सुरक्षा, संचार प्रणाली और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के सामरिक सहयोग को नई मजबूती मिलेगी।विशेषज्ञों का मानना है कि यह यात्रा केवल आर्थिक और तकनीकी सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी को भी नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है। दोनों देशों ने भविष्य में व्यापार, निवेश, नवाचार और सुरक्षा सहयोग को और विस्तार देने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फैसला सुरक्षित

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए कथित यौन उत्पीड़न के मामले में पूर्व भारतीय जनता पार्टी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस के केस पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने बताया कि इस मामले में दोषी ठहराने या बरी करने का अंतिम आदेश 3 अगस्त 2026 को सुनाया जाएगा। न्यायाधीश पंवार ने महिला पहलवानों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन, बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन और दिल्ली सरकार के सरकारी वकील की अंतिम दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा। यह पूरा मामला छह महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है, जिनकी शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को बृजभूषण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें धारा 354, धारा 354A, धारा 354D और धारा 506(1) शामिल है। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने 10 मई 2024 को पांच महिला पहलवानों के उत्पीड़न के मामले में सिंह के खिलाफ आरोप तय किए थे। कोर्ट ने माना था कि उनके खिलाफ केस चलाने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

पेट्रोल-डीजल के दाम कटौती पर बोले-हरदीप सिंह पुरी

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद सरकार ने वित्तीय उपायों के जरिए इसका अतिरिक्त बोझ आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने दिया है।पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संभावित कटौती को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटने का असर तुरंत खुदरा ईंधन की कीमतों पर दिखाई नहीं देता। इसकी वजह यह है कि कच्चे तेल की खरीद, समुद्री परिवहन, रिफाइनिंग और वितरण की पूरी प्रक्रिया में समय लगता है। इसलिए वैश्विक कीमतों में बदलाव का प्रभाव कुछ समय बाद ही घरेलू बाजार में दिखाई देता है।हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हाल के वर्षों में दुनिया ने कई बड़े भू-राजनीतिक संकटों का सामना किया, लेकिन भारत ने हर परिस्थिति में अपने नागरिकों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता देश की ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखना और उपभोक्ताओं को राहत देना है।

बहराइच में अवैध गोदाम पर छापा,दवा कारोबारी गिरफ्तार

नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कार्रवाई है। जिला औषधि निरीक्षक विनय कृष्ण ने बताया कि गोपनीय सूचना मिलने के बाद बुधवार को औषधि विभाग, दरगाह शरीफ थाना और रुपईडीहा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने परसौरा गांव स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। तलाशी के दौरान वहां पेटियों में बड़ी मात्रा में रखी कोडीनयुक्त कफ सिरप की 8,000 से अधिक शीशियां बरामद हुईं। जांच में सामने आया कि गोदाम में रखी गई दवाओं के भंडारण के लिए कोई वैध लाइसेंस नहीं था।अधिकारियों के अनुसार आरोपी के पास दूसरे पते पर दवा विक्रय का लाइसेंस जरूर था, लेकिन

जिस स्थान पर कफ सिरप का भंडारण किया गया था, वह पूरी तरह अवैध था। बरामदगी के बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जब्त की गई दवाओं के स्रोत, आपूर्ति श्रृंखला और संभावित खरीदारों की भी जांच की जा रही है।बहराइच में हाल के दिनों में कोडीनयुक्त कफ सिरप की बरामदगी का यह दूसरा बड़ा मामला है। इससे दो दिन पहले रुपईडीहा क्षेत्र के एक आयुर्वेदिक दवा स्टोर पर हुई छापेमारी में भी 2,000 से अधिक कोडीनयुक्त कफ सिरप की शीशियां जब्त की गई थीं। उस मामले में भी स्टोर संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।भारत-नेपाल सीमा के निकट स्थित होने के कारण बहराइच लंबे समय से नशीली दवाओं की तस्करी के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। पुलिस अब दोनों मामलों के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि बरामद कफ सिरप की खेप को नेपाल या अन्य क्षेत्रों में अवैध रूप से भेजने की कोई साजिश तो नहीं थी। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

CISF ने तीन चीनी नागरिकों को अघोषित भारतीय नकदी के साथ हिरासत में लिया

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते एक बड़ा मामला सामने आया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों ने बृहस्पतिवार शाम को तीन चीनी नागरिकों को भारी मात्रा में अघोषित भारतीय नकदी के साथ हिरासत में लिया। आरोपियों के पास से कुल 18.95 लाख रुपये बरामद किए गए हैं, जिसके संबंध में वे कोई भी वैध दस्तावेज या संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और संदिग्ध परिस्थितियों के चलते तीनों यात्रियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क (कस्टम) विभाग के हवाले कर दिया गया है। सीआईएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना बृहस्पतिवार शाम करीब 4:30 बजे की है। ये तीनों चीनी नागरिक दिल्ली से शंघाई जाने वाली उड़ान पकड़ने के लिए आईजीआई हवाई अड्डे के टर्मिनल पर पहुंचे थे। सुरक्षा जांच (Security Check) के दौरान सीआईएसएफ कर्मियों को एक यात्री के सामान पर संदेह हुआ। जब उसके बैग की गहनता से तलाशी ली गई, तो उसमें से ₹6 लाख की नकद राशि बरामद हुई। हवाई अड्डे पर तय सीमा से अधिक नकदी ले जाने के नियमों के तहत जब सुरक्षाकर्मियों ने यात्री से पूछताछ की, तो वह नकदी के स्रोत (Source) या उसे ले जाने से जुड़े वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका।

कांग्रेस से नाराज हुए मनीष तिवारी, पाकिस्तान संबंधों को लेकर उठा विवाद

कभी कांग्रेस के असंतुष्ट गुट जी-23 के सदस्य रहे मनीष तिवारी एक बार फिर नाराज नजर आ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर संगठनात्मक फेरबदल के बाद जिस तरह उन्हें पूरी तरह किनारे कर दिया गया, उससे उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। चंडीगढ़ से लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने सीधे तौर पर तो पार्टी नेतृत्व पर हमला नहीं बोला, लेकिन उनके शब्दों में गहरी पीड़ा और असहमति साफ दिखाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि किसी व्यक्ति या संस्था में प्रतिभा और क्षमता होना क्या सबसे बड़ा दोष है? काश उनके पास असुरक्षाओं का कोई इलाज होता। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने उन्हें पिछले पैंतालीस वर्षों में बहुत कुछ दिया है और उन्होंने भी अपना पूरा जीवन पार्टी की सेवा में लगाया है। vदरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस

कमेटी ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के तहत कई महत्वपूर्ण समितियों की घोषणा की है। चरणजीत सिंह चन्नी को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया, विजय इंदर सिंगला को चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति की जिम्मेदारी दी गई, सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोर समिति का प्रमुख बनाया गया तथा अमर सिंह को घोषणा पत्र समिति की कमान सौंपी गई है। इसके साथ ही अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रताप सिंह बाजवा को विधायक दल का नेता बनाए रखने का निर्णय लिया गया। पार्टी ने तीन कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति की, लेकिन पंजाब कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में शामिल मनीष तिवारी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई।

हिन्दी जगत महामंच
www.tvbharatvarsh.in
tv भारतवर्ष
सच्ची खबर, सीधे आपके लिए
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक ई-पेपर
प्रदेश का नं. 1
प्रतिष्ठित हिन्दी न्यूज़
ई-पेपर

विज्ञापन दर

साईज	विजिटिंग कार्ड	क्वाटर पेज	हाफ पेज	फुल पेज (अंदर)	फुल पेज (कवर 2- 3)	फुल पेज (कवर 4- अंतिम)	(फ्रंट पेज)
रेट	₹ 3000	₹ 6000	₹ 10,000	₹ 20,000	₹ 25,000	₹ 30,000	₹ 100000

8601780000

भारत-जापान शिखर वार्ता

आर्थिक सुरक्षा, रक्षा और तकनीक सहयोग को मिली नई मजबूती

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी आपसी भरोसे, साझा मूल्यों और रणनीतिक हितों पर आधारित है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के बीच गुरुवार को नई दिल्ली में द्विपक्षीय शिखर वार्ता हुई। बैठक में दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने के लिए आर्थिक साझेदारी का नया फ्रेमवर्क पेश किया। साथ ही सैन्य उपकरणों के संयुक्त विकास के लिए रक्षा समझौता किया गया। इसके अलावा ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के कई फैसले लिए गए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे की पूरक हैं। सांस्कृतिक मूल्यों से लेकर आधुनिक तकनीक तक दोनों देशों की सोच और काम करने का तरीका काफी हद तक एक जैसा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत आपसी भरोसा है। मोदी ने बताया कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा के लिए एक साझा रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मैटेरियल्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा ताकि भविष्य में इन अहम क्षेत्रों में किसी तरह की बाधा न आए। दोनों नेताओं ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को नई मजबूती देने पर सहमति जताई है। इसके तहत सैन्य उपकरणों के संयुक्त विकास के लिए रक्षा समझौता किया गया। इसके अलावा ऊर्जा और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए कई नए कदमों का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। भारत-जापान बायोगैस पहल के तहत भारत में 1,000 बायोगैस और जैविक खाद संयंत्र लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे देश के गांवों में टिकाऊ विकास, समृद्धि और लोगों की आजीविका को नई मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी आपसी भरोसे, साझा मूल्यों और रणनीतिक हितों पर आधारित है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत और जापान के रिश्तों को 2014 में स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का दर्जा मिला था। दोनों देशों के बीच अब 70 से ज्यादा स्तरों पर नियमित बातचीत और सहयोग का तंत्र है। 2027 में भारत और जापान अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे करेंगे। इस दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, आर्थिक सुरक्षा, विज्ञान-तकनीक, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग लगातार बढ़ा है। जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची तीन दिन की भारत यात्रा पर हैं। गुरुवार सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया जिसके बाद उन्होंने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी यात्रा का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देशों के साझा प्रयास हिंद-प्रशांत क्षेत्र और दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह शिखर वार्ता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने उसे और मजबूत बनाने तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर है।

अमेरिका-ईरान वार्ता का दौर खत्म, स्थायी समझौते पर नहीं बनी सहमति

कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच दो दिनों तक चली अप्रत्यक्ष वार्ता गुरुवार को समाप्त हो गई। हालांकि दोनों देशों ने बातचीत को सकारात्मक बताया, लेकिन किसी स्थायी शांति समझौते या परमाणु कार्यक्रम पर कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी। वार्ता का मुख्य केंद्र होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री यातायात की सुरक्षा और ईरान की जमी हुई विदेशी संपत्तियों से जुड़े मुद्दे रहे।सूत्रों के अनुसार, वार्ता में दोनों पक्षों ने जून में हुए अंतरिम समझौते के क्रियान्वयन की समीक्षा की। ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में अपने अधिकारों और भविष्य की व्यवस्था पर जोर दिया, जबकि अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की निर्बाध आवाजाही को अपनी प्राथमिकता बताया। वार्ता के दौरान परमाणु कार्यक्रम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कोई निर्णायक चर्चा नहीं हुई, जिससे व्यापक शांति समझौते की संभावना फिलहाल टलती दिखाई दे रही है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता के बाद कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और संवाद जारी रहना सकारात्मक संकेत है। दूसरी ओर, ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी अंतिम समझौते से पहले उनके राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान आवश्यक होगा। कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए कहा कि वार्ता में कुछ विषयों पर सकारात्मक प्रगति हुई है, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद अभी भी बरकरार हैं।वार्ता के बाद अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में भी प्रतिक्रिया देखने को मिली। निवेशकों को उम्मीद है कि यदि भविष्य में दोनों देशों के बीच तनाव और कम होता है तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति अधिक स्थिर हो सकती है। इसी उम्मीद के बीच कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक स्थायी समझौता नहीं होता, तब तक पश्चिम एशिया में अनिश्चितता बनी रहेगी।

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर गंभीर आरोप लगाया

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

ऊधम सिंह नगर में किच्छा में एक फार्म है जिसको लेकर विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल वहां स्थित 4 एकड़ के खान फार्म को लेकर आज भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस PC में उन्होंने वाड्रा परिवार और विशेषतौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा पर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के एक विधायक कुछ लोगों के साथ उस फार्म पर गए और वहां रह रही बुजुर्ग महिला को फार्म खाली करने के लिए धमकाया है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि PC में प्रदीप भंडारी ने क्या कुछ कहा। PC में बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर आरोप लगाते हुए कहा, 'सायरा वाड्रा जो प्रियंका वाड्रा की जेठानी हैं, वो इस (खान फार्म) जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। जब यह लैंड एक सिविल डिस्प्यूट है और यह बात गांधी-वाड्रा परिवार को समझ आ गया है कि कानूनी तौर पर इस 4 एकड़ की जमीन पर सायरा वाड्रा कब्जा नहीं कर सकती हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के किच्छा विधायक और प्रियंका वाड्रा के करीबी तिलक राज बेहड़ कल देर रात को 100 लोगों के साथ उस जमीन पर जाते हैं और वहां जो 90 वर्षीय महिला है, उन्हें धमकाते हैं कि अगर उन्होंने यह जमीन खाली नहीं की तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। यह आरोप खुद उस महिला यानी नसरीन खान ने लगाया है। भाजपा प्रवक्ता के आरोपों के मुताबिक इस मामले में आरोप लगाते हुए नसरीन खान ने कहा, 'मैं अपने फार्म पर मौजूद हूं। यहां कुछ लोग आए हैं जो कांग्रेस के हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरी जमीन का कब्जा वाड्रा परिवार को दे दें।' प्रदीप भंडारी ने आगे कहा कि उन्होंने यानी नसरीन खान ने सायरा वाड्रा का नहीं बल्कि वाड्रा परिवार का नाम लिया है।प्रदीप भंडारी ने आगे कहा, 'हम प्रियंका वाड्रा से यह सवाल पूछना चाहते हैं कि अपनी जेठानी को एक जमीन दिलाने के लिए ये गांधी-वाड्रा परिवार किस हद तक जाएगा।

यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का भीषण हमला कई लोगों की मौत

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर तेज हो गया है। गुरुवार को रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसमें कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हमले के बाद शहर के कई इलाकों में आग लग गई, आवासीय इमारतों और सार्वजनिक ढांचे को नुकसान पहुंचा तथा बचाव दल देर रात तक राहत एवं खोज अभियान चलाते रहे।यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि हमले का मुख्य निशाना राजधानी के आवासीय और रणनीतिक क्षेत्र थे। हवाई हमले की चेतावनी जारी होने के बाद बड़ी संख्या में लोग बंकरों में शरण लेने को मजबूर हुए। कई इलाकों में बिजली और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हुईं। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन सहायता बढ़ा दी है।राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि रूस लगातार नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने पश्चिमी देशों से यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सैन्य सहायता उपलब्ध कराने की अपील की। दूसरी ओर रूस ने अपने हमलों को सैन्य ठिकानों पर केंद्रित कार्रवाई बताया है, हालांकि यूक्रेन ने इस दावे को खारिज किया है। हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता भी बढ़ गई है। कई पश्चिमी देशों ने नागरिक क्षेत्रों पर हुए हमलों की निंदा करते हुए युद्ध को रोकने और कूटनीतिक समाधान तलाशने की आवश्यकता दोहराई है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने भी दोनों पक्षों से संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के हमलों से शांति वार्ता की संभावनाओं को एक बार फिर झटका लग सकता है और क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है। फिलहाल कीव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और राहत एजेंसियां प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने में जुटी हैं।

पश्चिम एशिया के पूरे नेटवर्क पर बहाल हुई सेवाएं टाटा ग्रुप की एयर इंडिया एक्सप्रेस ने घोषणा

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस ने घोषणा की है कि उसने पश्चिम एशिया के सभी गंतव्यों के लिए अपनी उड़ान सेवाएं फिर से बहाल कर दी हैं। ओमान और कुवैत के लिए भी उड़ानें दोबारा शुरू होने के साथ अब एयरलाइन का पूरा वेस्ट एशिया नेटवर्क फिर से सामान्य हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के अनुसार, कोझिकोड-सलालाह (ओमान) रूट पर उड़ानें 2 जुलाई से फिर शुरू हो गई हैं। वहीं कोझिकोड-कुवैत सेवा 3 जुलाई से बहाल होगी, जबकि बेंगलुरु-कुवैत रूट पर उड़ानों का संचालन 4 जुलाई से शुरू किया जाएगा। आने वाले दिनों में इन रूटों पर उड़ानों की संख्या भी धीरे-धीरे बढ़ाई जाएगी ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। एयरलाइन ने बताया कि क्षेत्र में हालात सामान्य होने के बाद अब उसके पश्चिम एशिया के सभी गंतव्यों पर उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। इससे उन हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी, जिनकी यात्रा योजनाएं पिछले कुछ समय से प्रभावित थीं। फिलहाल एयर इंडिया एक्सप्रेस भारत के 18 शहरों को पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों से जोड़ते हुए हर हफ्ते करीब 780 उड़ानों का संचालन करती है। इससे नौकरी, कारोबार और पारिवारिक कारणों से यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी सुविधा मिलती है। पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कुछ समय पहले ओमान, कुवैत सहित कुछ रूटों पर अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी थीं। हालात में सुधार के बाद अब कंपनी ने चरणबद्ध तरीके से सभी सेवाएं बहाल करने का फैसला लिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास इस समय 100 से अधिक विमानों का बेड़ा है। एयरलाइन हर दिन 500 से ज्यादा उड़ानों का संचालन करती है और 43 घरेलू तथा 16 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ती है। कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में पश्चिम एशिया के रूटों पर मांग बढ़ने के अनुसार उड़ानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इससे भारतीय यात्रियों के साथ-साथ खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

संपादक की कलम से

युवाओं की आवाज और शिक्षा व्यवस्था की चुनौती: राजस्थान के कोटा से शुरू हुआ 'छात्रों की गूंज' अभियान एक बार फिर देश की शिक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रक्रियाओं और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ले आया है। चाहे इस अभियान को राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए या सामाजिक पहल के रूप में, यह तथ्य निर्विवाद है कि देश का युवा वर्ग आज कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी, सीमित रोजगार अवसर और बढ़ता मानसिक दबाव लाखों विद्यार्थियों के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं।भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। यह स्थिति देश के लिए एक बड़ी शक्ति भी हो सकती है और चुनौती भी। यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निष्पक्ष अवसर और रोजगार उपलब्ध कराए जाएं तो वे राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन यदि उनकी आकांक्षाओं और मेहनत को उचित मंच नहीं मिलता, तो निराशा और असंतोष का माहौल पैदा होना स्वाभाविक है।पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों और राष्ट्रीय स्तर की कई परीक्षाओं में पेपर लीक तथा अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। एक छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम करता है, परिवार अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च करता है, लेकिन जब परीक्षा की निष्पक्षता ही संदिग्ध हो जाए तो युवाओं का भरोसा डगमगाना स्वाभाविक है। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि लाखों सपनों पर सीधा आघात है।इसके साथ ही समाज में सफलता की परिभाषा को लेकर भी गंभीर पुनर्विचार की आवश्यकता है। आज भी डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सेवक या कुछ चुनिंदा पेशों को ही सफलता का पर्याय मान लिया जाता है। इससे बड़ी संख्या में युवा अनावश्यक दबाव में आ जाते हैं। नई अर्थव्यवस्था के दौर में कौशल आधारित रोजगार, उद्यमिता, नवाचार, खेल, कला और रचनात्मक क्षेत्रों में भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं। शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करवाना नहीं, बल्कि व्यक्तित्व और प्रतिभा का समग्र विकास होना चाहिए।हालांकि इस विषय पर राजनीति भी होती रही है। विपक्ष सरकार को घेरता है और सरकार सुधारों का दावा करती है। लेकिन युवाओं के भविष्य जैसे संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रखा जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि सभी राजनीतिक दल, शिक्षा विशेषज्ञ और नीति निर्माता मिलकर ऐसी व्यवस्था विकसित करें जिसमें परीक्षाएं पूरी तरह सुरक्षित हों, भर्ती प्रक्रियाएं समयबद्ध हों और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हों।देश का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में है। इसलिए उनकी समस्याओं को सुनना, समझना और उनका समाधान करना केवल राजनीतिक दायित्व नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता है। यदि शिक्षा और रोजगार व्यवस्था में पारदर्शिता, गुणवत्ता और विश्वास स्थापित किया जा सके, तो भारत की युवा शक्ति वास्तव में देश की सबसे बड़ी पूंजी सिद्ध होगी।

मणिपुर हिंसा पर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला

बोले- राज्य को शांति नहीं, राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए

राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि मणिपुर केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि मानवीय और राजनीतिक संवेदनशीलता का मामला है। उन्होंने केंद्र सरकार से सभी पक्षों के साथ संवाद बढ़ाने, राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने और प्रभावित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की घटनाओं के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार बिगड़ते हालात इस बात का संकेत हैं कि केंद्र और राज्य सरकार स्थिति को सामान्य बनाने में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लंबे समय से जारी तनाव के बावजूद प्रभावी राजनीतिक पहल नहीं होने के कारण आम लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है।राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि मणिपुर केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि मानवीय और राजनीतिक संवेदनशीलता का मामला है। उन्होंने केंद्र सरकार से सभी पक्षों के साथ संवाद बढ़ाने, राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने और प्रभावित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में शांति बहाल करने के लिए विश्वास बहाली के ठोस कदम उठाने होंगे और केवल प्रशासनिक कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है।कांग्रेस के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, राहत शिविरों की व्यवस्था और विभिन्न समुदायों के बीच संवाद की प्रक्रिया जारी है। पार्टी ने आरोप लगाया कि विपक्ष संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, जबकि सरकार का पूरा ध्यान हालात सामान्य करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मणिपुर का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। संसद के आगामी सत्र और विभिन्न राजनीतिक मंचों पर भी इस विषय पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। विपक्ष जहां सरकार की नीतियों और संकट प्रबंधन पर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्तापक्ष अपने प्रयासों और सुरक्षा उपायों का हवाला देकर आलोचनाओं का जवाब दे रहा है।विशेषज्ञों का कहना है कि मणिपुर में स्थायी शांति के लिए केवल सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि राजनीतिक संवाद, सामाजिक विश्वास की बहाली और पुनर्वास कार्यक्रमों को समान महत्व देना होगा। फिलहाल राज्य के हालात पर केंद्र सरकार की लगातार नजर बनी हुई है और प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के संकेत हैं, जिससे यह राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल हो गया है।

कांग्रेस नेता ने की ईरान जाने की पुष्टि,सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार में शामिल होगी कांग्रेस

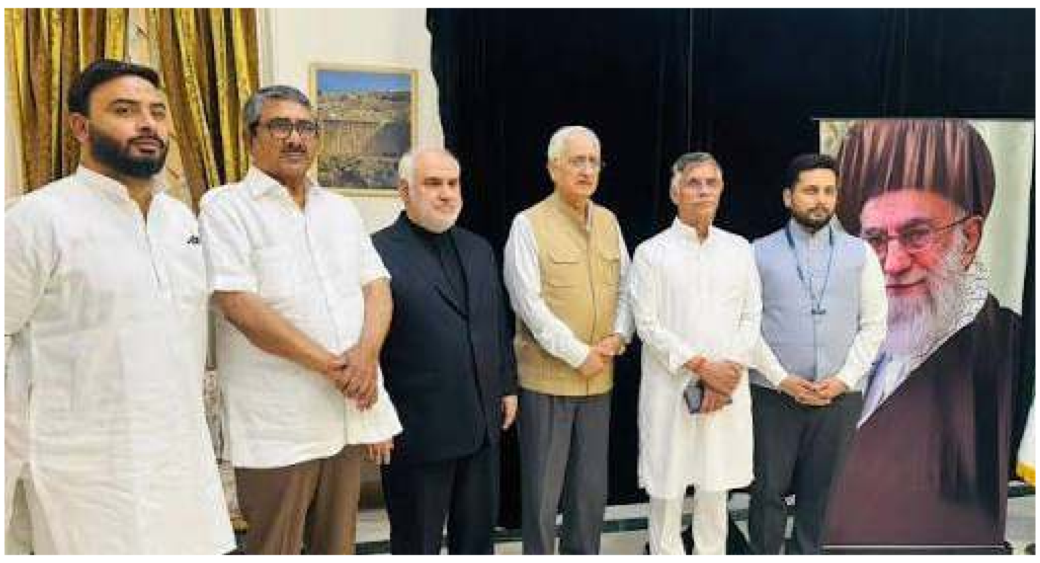

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में कांग्रेस आला कमान ने कांग्रेस वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद को ईरान भेजने का फैसला किया है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने गुरुवार को घोषणा की है कि वह ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। एएनआई से बात करते हुए पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने ईरान जाने की पुष्टि की और कहा कि वे इस ऐतिहासिक और संवेदनशील मौके पर पार्टी की तरफ से शामिल होने के लिए तेहरान जाएंगे। आपको बता दें कि तेहरान प्रशासन ने इस अंतिम संस्कार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद और नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा को औपचारिक निमंत्रण भेजा था, जिसके अगले ही दिन कांग्रेस की ओर से यह फैसला सामने आया। आपको बता दें कि फरवरी के आखिरी सप्ताह में अमेरिका और इजराइल के एक संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ईरान में उनके बेटे मोजतबा खामेनेई ने उनकी जगह ली है। ईरानी अधिकारियों द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, खामेनेई के लिए तीन दिनों के सार्वजनिक अंतिम संस्कार की रस्में 4 जुलाई से शुरू होने जा रही हैं। ईरानी अधिकारियों के अनुसार 7 जुलाई को राजधानी तेहरान के दक्षिण में स्थित पवित्र शहर कोम में विशेष कार्यक्रम होंगे, और 9 जुलाई को उनके गृहनगर, उत्तर-पूर्वी ईरान के पवित्र शहर मशहद में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक (दफन) किया जाएगा।इस राजकीय अंतिम संस्कार के लिए ईरान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया था। हालांकि, भारत सरकार ने नई दिल्ली की ओर से देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (रिटायर्ड) और केंद्रीय मंत्री पवित्र मार्गेरिटा को तेहरान भेजने का फैसला किया है।

तीन राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान

राजनीतिक दलों ने तेज की तैयारियां

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन रिक्त विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी। आयोग के अनुसार इन सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही संबंधित राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और प्रमुख दलों ने उम्मीदवारों के चयन तथा चुनाव प्रचार की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।निर्वाचन आयोग ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आयोग ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को चुनावी नियमों का पालन करने तथा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने में सहयोग करने की अपील की है। मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित राज्य प्रशासन को दिए गए हैं।उपचुनाव की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों ने अपने-अपने संगठनात्मक स्तर पर बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। राजनीतिक दल इन सीटों को आगामी चुनावी समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रहे हैं। भाजपा ने दावा किया है कि जनता विकास और सुशासन के आधार पर उसे समर्थन देगी, जबकि कांग्रेस और विपक्षी दलों का कहना है कि वे स्थानीय मुद्दों और जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे। उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी दलों में मंथन जारी है।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भले ही उपचुनाव केवल तीन सीटों पर हो रहे हों, लेकिन इनके परिणाम राष्ट्रीय राजनीति के लिए संकेतक साबित हो सकते हैं। कई बार उपचुनाव के नतीजे सरकार और विपक्ष दोनों के लिए जनमत का आकलन करने का अवसर बनते हैं। इसलिए सभी प्रमुख दल इन चुनावों को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। अब उम्मीदवारों की घोषणा, प्रचार अभियान और स्थानीय मुद्दों पर होने वाली चुनावी बहस पर सभी की नजर रहेगी। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी।

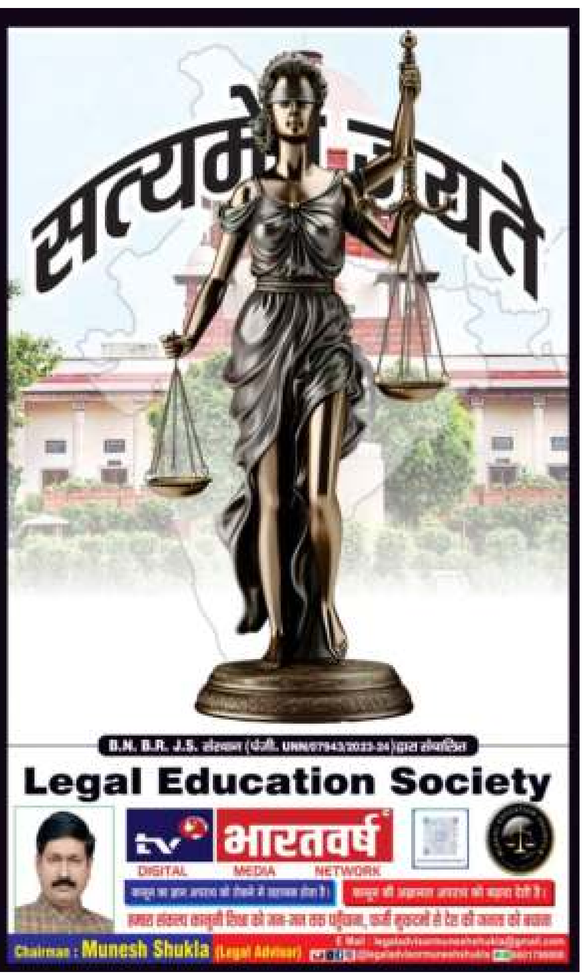

UAE में टीचर बनने का सपना
भारतीय B.Ed. ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा अवसर

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भारतीय टीचर्स के बीच जॉब के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन चुका है। तेजी से बढ़ते प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर, टैक्स-फ्री सैलरी, वर्ल्ड-क्लास लाइफस्टाइल और बड़ी संख्या में भारतीयों की मौजूदगी की वजह से UAE में वे सारी सुविधाएं मिलती हैं, जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है। यही वजह है कि अब भारत के हजारों B. Ed. ग्रेजुएट अपने करियर को नया रूप देने के लिए UAE जाना चाहते हैं। अच्छी बात ये है कि अगर आपने भारत में बैचलर ऑफ एजुकेशन (B. Ed) की डिग्री हासिल की है, तो आप आराम से UAE में जाकर जॉब कर सकते हैं। इस क्वालिफिकेशन के जरिए UAE में आसानी से टीचिंग करियर की शुरुआत की जा सकती है। हालांकि, यहां टीचर बनने से पहले कुछ लाइसेंसिंग एग्जाम और जरूरी क्वालिफिकेशन भी हासिल करने की जरूरत है। आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे, ताकि आप भी UAE में टीचर बन पाएं। संयुक्त अरब अमीरात में टीचर बनने से पहले आपको ये समझना होगा कि यहां का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? इसके पीछे की वजह ये है कि हर एक अमीरात के अपने-अपने नियम-कायदे हैं, जिनके बारे में जानने के बाद ही आसानी से टीचिंग की जॉब की जा सकती है।

मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन (शिक्षा मंत्रालय): ये केंद्र सरकार के अधीन आने वाली संस्था है, जो UAE में सभी तरह की एजुकेशन से जुड़ी चीजें देखती है। इसका काम सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूलों की निगरानी करना है, जो ज्यादातर आबू धाबी और उत्तरी अमीरात में स्थित हैं। नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी (KHDA): KHDA खास तौर पर दुबई के प्राइवेट स्कूलों को रेगुलेट करता है। अगर आप दुबई के किसी प्राइवेट स्कूल (जैसे ब्रिटिश, अमेरिकन, IB, इंडियन/CBSE करिकुलम वाले स्कूल) में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप पर KHDA के नियम लागू होंगे।

आबू धाबी एजुकेशन एंड नॉलेज (ADEK): इसका काम आबू धाबी के प्राइवेट स्कूलों को रेगुलेट करना है। अन्य अमीरात (शारजाह, अजमान, उम्म अल-क्वैन, फुजेराह, रास अल-खैमाह): यहां के प्राइवेट स्कूल मंजूरी के लिए सीधे शिक्षा मंत्रालय के साथ काम करते हैं। ज्यादातर भारतीय B. Ed. होल्डर्स के लिए प्राइवेट स्कूल ही जॉब करने का सबसे आसान रास्ता है। खासकर CBSE/भारतीय करिकुलम वाले बड़ी संख्या में स्कूल और साथ ही ब्रिटिश और अमेरिकन करिकुलम वाले स्कूलों में नौकरी पाना आसान होता है। इसके पीछे की वजह ये है कि सरकारी स्कूलों में आम तौर पर विदेशी टीचर्स की हायरिंग कम ही होती है, क्योंकि वहां राष्ट्रीयता या एक्सपीरियंस से जुड़ी शर्तें होती हैं। UAE सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, UAE में टीचर के तौर पर कानूनी रूप से काम करने के लिए कम से कम संबंधित क्षेत्र (जिस सब्जेक्ट में पढ़ाना है) में बैचलर डिग्री (4 साल की यूनिवर्सिटी डिग्री) या उससे ऊपर की डिग्री होनी चाहिए। B. Ed डिग्री होने की वजह से भारतीय टीचर्स पहले से ही इस जरूरी शर्त को पूरा कर लेते हैं और कई मामलों में तो इससे भी बेहतर योग्यता रखते हैं।

नई जॉब की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट (NAEL) को ऑपरेटर और जूनियर असिस्टेंट की जरूरत

नई जॉब की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट है। प्रयागराज की नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड (NAEL) को ऑपरेटर और जूनियर असिस्टेंट की जरूरत है। इसके लिए कंपनी की तरफ से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट www.nael.co.in पर एप्लिकेशन प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड (NAel) हिन्दुस्तान एयनोटिक्स लिमिटेड (HAL) की पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। जिन लोगों को रक्षा, एसरोस्पेस और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में करियर बनाना है, उन अभ्यर्थियों के लिए यह अच्छा मौका हो सकता है। पदानुसार सभी पदों के लिए अलग-अलग एलिजिबिलिटी मांगी गई है।

ऑपरेटर एसएस (इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक FTE बेसिस): मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास के साथ 2 साल का फुल टाइम रेगुलर ITI (NTC) इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में किया हो।

ऑपरेटर एसएस (फिटर FTE बेसिस): 10वीं पास के साथ फुल टाइम आईटीआई फिटर ट्रेड में किया हो।

ऑपरेटर एसएस (इलेक्ट्रीशियन FTE बेसिस): 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के साथ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट हासिल किया हो।

जूनियर असिस्टेंट (IMM): मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फुल टाइम बीकॉम/बीएससी की डिग्री हासिल की हो। साथ में 6 महीने का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या फुल टाइम बीसीए की हो।

जूनियर असिस्टेंट (HR): फुल टाइम बीए/बीएससी/बीबीए/बीएसडब्ल्यू की डिग्री और टाइपिंग/कंप्यूटर में कम से कम 6 महीने का सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो।

जूनियर असिस्टेंट (Fin.): बी.कॉम/बीबीए की डिग्री के साथ 6 महीने का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हासिल किया हो।

जूनियर असिस्टेंट (IT): फुल टाइम बीसीए/बीएससी (कंप्यूटर/आईटी) की डिग्री पूरी की हो। जिन कैंडिडेट्स ने पार्ट टाइम/कॉरेपॉन्टेंस/डिस्टेंस एजुकेशन/ई-लर्निंग शैक्षिक योग्यता पूरी की हैं, वो आवेदन के योग्य नहीं होंगे।

भारत बनाम इंग्लैंड पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला बारिश के कारण पूरा नहीं हो पाया

टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलिया की नजर 7वें खिताब पर

ICC वूमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी को लेकर बड़ा संकेत दिया है। टीम मैनेजमेंट ने साफ किया है कि अगर पेरी पूरी तरह फिट नहीं भी हो पाती हैं, तब भी उन्हें खिताबी मुकाबले में उतारने पर विचार किया जा सकता है। वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर अनुभवी खिलाड़ियों की अहमियत को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया कोई जोखिम लेने से पीछे नहीं हटना चाहता। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य कोच शेली निट्शके ने 2 जुलई को मीडिया से बातचीत में कहा कि पेरी की फिटनेस को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सेमीफाइनल के बाद टीम ने अभ्यास भी नहीं किया है, इसलिए उनकी स्थिति का पूरा आकलन अभी बाकी है। हालांकि, टीम को उम्मीद है कि फाइनल तक वह खेलने के लिए तैयार हो जाएंगी। पेरी वेस्टइंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल में बल्लेबाजी के दौरान चोट के कारण मैदान से बाहर चली गई थीं। टीम ने इसे एहतियाती कदम बताया था। ऑस्ट्रेलिया के अनुसार उनकी क्वाड में हल्की परेशानी महसूस हुई थी, इसलिए उन्हें आगे खेलने का जोखिम नहीं दिया गया। शेली निट्शके ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो टीम पेरी को पूरी तरह फिट हुए बिना भी मैदान पर उतार सकती है। उन्होंने माना कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में फैसले सामान्य मैचों से अलग होते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पेरी खुद भी तभी खेलना चाहेंगी जब उन्हें लगे कि वह बल्लेबाजी, फील्डिंग और विकेटों के बीच दौड़ने में टीम के लिए प्रभावी योगदान दे सकती हैं। एलिस पेरी इस पूरे टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल बल्लेबाज रही हैं। उन्होंने अब तक 185 रन बनाए हैं। उनका औसत 46.25 और स्ट्राइक रेट 135.03 रहा है। पाकिस्तान और भारत के खिलाफ उन्होंने शानदार अर्धशतक जड़े थे। खासकर भारत के खिलाफ मुश्किल परिस्थिति में खेली गई उनकी पारी ने ऑस्ट्रेलिया को यादगार जीत दिलाई थी।

IND बनाम SL टेस्ट की तारीखें कंन्फर्म

श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) साइकिल के तहत 15 अगस्त से 27 अगस्त के बीच दो टेस्ट की सीरीज के लिए भारतीय टीम की मेजबानी करने की पुष्टि की है। इस सीरीज का पहला मुकाबला गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में और दूसरा मैच सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (SSC) कोलंबो में खेला जाना है। ये दोनों मैच भारतीय समयानुसार, सुबह 10:00 बजे शुरू होंगे। बता दें कि दोनों एशियाई टीमों ने 2022 के बाद से एक-दूसरे के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है। भारत ने टेस्ट सीरीज का आखिरी श्रीलंका दौरा 2017 में किया था। दरअसल, रिपोर्ट्स में मैचों की तारीखें और जगहों का पहले ही पता चल गया था। अब श्रीलंका क्रिकेट ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टी की है। फिलहाल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडिया ए को गॉल में 2 प्रथम श्रेणी मैच खेलने के लिए श्रीलंका भेजा है। इंडिया ए ने पहले मैच में श्रीलंका ए को हराया, जबकि दूसरा मैच अभी जारी है। बताया जा रहा है कि जनवरी में श्रीलंका क्रिकेट ने पहले से मौजूद 2 टेस्ट मैचों के साथ तीन टी20 इंटरनेशनल मैच की सीरीज जोड़ने की रिक्वेस्ट की थी। बीसीसीआई ने साइक्लोन दितवाह से प्रभावित लोगों के लिए फंड जुटाने के लिए गुडविल जेस्चर के तौर पर इसे मान लिया था, जिससे श्रीलंका के कई हिस्सों में बहुत नुकसान हुआ था। खबर थी कि बीसीसीआई ने श्रीलंका टूर पर व्हाइट-बॉल मैच खेलने से मना कर दिया है। जबकि श्रीलंका क्रिकेट उन्हें लंबे समय तक रुकने के लिए मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन, बिजी शेड्यूल की वजह से टी20 मुमकिन नहीं हैं। लंका प्रीमियर लीग (LPL 2026) सीजन 9 अगस्त को खत्म होगा। इसलिए 15 अगस्त को टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले 3 मैचों की मेजबानी करना मुमकिन नहीं है। इसलिए, टी20 इंटरनेशनल 27 अगस्त को टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद ही खेले जा सकते हैं। हालांकि, भारत के सितंबर में बांग्लादेश का टूर करने और सितंबर में घर पर अफगानिस्तान से खेलने की उम्मीद है।

इस्माइल सैबारी को डच क्लब पीएसवी से 542 करोड़ रुपये में साइन किया

एक तरफ जहां पूरी दुनिया पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खुमार छाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जर्मन फुटबॉल की सबसे टीम बायर्न म्यूनिख ने टूर्नामेंट के बीच में ही एक बहुत बड़ा ट्रांसफर धमाका कर दिया है। बायर्न म्यूनिख ने नीदरलैंड्स के मशहूर डच क्लब पीएसवी आइंडहोवन से खेल रहे मोरक्को के 25 साल के स्टार अटैकिंग मिडफील्डर इस्माइल सैबारी को आधिकारिक तौर पर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इस उभरते हुए युवा खिलाड़ी के टैलेंट को देखते हुए बायर्न म्यूनिख ने उनके साथ साल 2031 तक का एक बेहद लंबा और सुरक्षित कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है।इस डील को लेकर फुटबॉल जगत में ट्रांसफर फीस की भी काफी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्ल्ड कप के ठीक बीचोंबीच हुई इस मेगा डील को पक्का करने के लिए बायर्न म्यूनिख ने लगभग 50 मिलियन यूरो, यानी करीब 542 करोड़ भारतीय रुपये की एक बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर फीस के रूप में चुकाई है। दरअसल, यह ट्रांसफर पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा में था और अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि टूर्नामेंट के दौरान जब मोरक्को की टीम न्यू जर्सी में अभ्यास कर रही थी, तब सैबारी इस ट्रांसफर से पहले होने वाले मेडिकल टेस्ट के लिए अपने एक ट्रेनिंग सेशन में भी शामिल नहीं हुए थे, ताकि वे इस जर्मन जायंट क्लब के साथ अपनी डील को समय रहते अंतिम रूप दे सकें। इस्माइल सैबारी ने चालू फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपनी राष्ट्रीय टीम मोरक्को के लिए जिस स्तर का प्रदर्शन किया है, उसी का नतीजा है कि दुनिया के सबसे बड़े क्लबों में से एक ने उन पर इतना बड़ा दांव खेला है। मोरक्को को वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 तक पहुंचाने में सैबारी की भूमिका सबसे अहम रही है। उन्होंने टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में खेलते हुए मोरक्को के तीनों मैचों में लगातार तीन शानदार गोल दागे। यही नहीं, सोमवार को नीदरलैंड्स जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेले गए राउंड ऑफ 32 के बेहद दबाव वाले नॉकआउट मुकाबले में जब मैच पेनल्टी शूटआउट में गया, तो सैबारी ने ही अंतिम और विनिंग पेनल्टी को ठंडे दिमाग से गोल में बदलकर मोरक्को को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी।

लोगों ने उठाए सिविक सेंस पर सवाल

कोच्चि वॉटर मेट्रो में करने लगे गरबा

केरल की कोच्चि वॉटर मेट्रो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ यात्री चलती नाव के अंदर गरबा करते नजर आते हैं.

जहां कुछ लोगों ने इसे संस्कृति और खुशी का खूबसूरत पल बताया, वहीं कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या सार्वजनिक परिवहन में इस तरह का डांस करना सही है? यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर क्रिस्टिन ने शेयर किया है. उन्होंने बताया कि वह फोर्ट कोच्चि जा रहे थे, तभी वॉटर मेट्रो का शांत सफर अचानक संगीत और गरबा की धुनों से भर गया. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि यह एक यादगार पल था.

लेकिन साथ ही लोगों से सवाल भी पूछा कि क्या इसे सिर्फ एक खुशनुमा पल माना जाए या फिर सार्वजनिक परिवहन के नियमों का उल्लंघन? वायरल वीडियो में कुछ यात्री वॉटर मेट्रो के अंदर गरबा करते दिखाई देते हैं. बाकी यात्री अपनी सीटों पर बैठे हुए यह नजारा देखते नजर आते हैं.

11 साल बाद बताई वजह

अमेजन की जॉब छोड़ क्यों चुना ऑटो चलाना?

आज के समय में अमेजन जैसी बड़ी कंपनी में जॉब करना लाखों युवाओं का सपना होता है. अच्छी सैलरी, करियर ग्रोथ और कॉर्पोरेट लाइफ के लिए लोग सालों तक मेहनत करते हैं. लेकिन हैदराबाद के एक शख्स ने ऐसी जॉब खुद छोड़ दी. वजह सुनकर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि हर किसी के लिए सफलता का मतलब एक जैसा नहीं होता. यह कहानी है कुमार की, जो कभी अमेजन में नौकरी करते थे. लेकिन उन्होंने कॉर्पोरेट दुनिया छोड़कर ऊबर चलाने का फैसला किया. वजह न तो जॉब से परेशानी थी और न ही किसी तरह की मजबूरी. उन्होंने सिर्फ इसलिए यह फैसला लिया, क्योंकि उन्हें गाड़ी चलाना बेहद

पसंद है. यह कहानी सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट क्रिएटर चेतना सिंह ने इंस्टाग्राम पर शेयर की. वह ऊबर से सफर कर रही थीं, तभी उनकी बातचीत ड्राइवर कुमार से हुई. बातचीत के दौरान पता चला कि कुमार पहले अमेजन में जॉब करते थे. जब उन्होंने पूछा कि इतनी बड़ी कंपनी की जॉब छोड़ने की वजह क्या थी, तो कुमार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उन्हें ड्राइविंग करना पसंद है. उनके लिए यह सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ने का एक तरीका है. कुमार बताते हैं कि उन्हें अलग-अलग राज्यों और देशों से आने वाले लोगों से मिलना अच्छा लगता है.

बंजी जंपिंग केस में नर्स का खुलासा!

130 फीट से गिरने के बाद भी जिंदा थी लड़की

ब्राजील में 130 फीट ऊंचे पुल से बंजी जंपिंग के दौरान हुए हादसे में 21 साल की एक लड़की की मौत हो गई. अब इस मामले को लेकर वहां मौजूद एक नर्स ने खुलासा किया है कि हादसे के बाद लड़की जिंदा थी.

ब्राजील में 130 फीट ऊंचे पुल से बंजी जंपिंग के दौरान बिना रस्सी नीचे कूदने पर एक लड़की की जान चली गई. अब इस मामले में एक नर्स ने दावा किया है कि उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी लड़की जिंदा थी और उसने उससे बात भी की. इस दर्दनाक हादसे के बाद अब उस ऑफ-ड्यूटी नर्स का बयान सामने आया है, जिसने घटना के तुरंत बाद लड़की तक पहुंचकर उसकी जान बचाने की कोशिश की थी. नर्स का कहना है कि पुल से गिरने के बाद भी लड़की कुछ समय तक जिंदा थी. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, नर्स ने उस लड़की से कहा था कि कोई नहीं मरेगा मेरी ड्यूटी में... नर्स ने बताया कि 130 फीट ऊंचे पुल से नीचे गिरने के बाद भी लड़की जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी. लड़की ने नर्स की आवाज सुनी भी थी और उससे बात भी की थी. लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी सांसें थम गईं. रायजा डायस नाम की नर्स घटना के समय वहीं मौजूद थी. जैसे ही लड़की के गिरने की खबर मिली, वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ी. रायजा ने ब्राजीलियाई टीवी नेटवर्क को बताया कि नीचे पहुंचने का रास्ता बेहद मुश्किल था. वहां खड़ी ढलान थी और नीचे उतरने के लिए सिर्फ एक रस्सी थी. पूरा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था. उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द लड़की तक पहुंचने की कोशिश में उनके हाथ तक छिल गए, लेकिन वह लगातार नीचे उतरती रहीं. नर्स के मुताबिक जब वह दुर्घटनास्थल पर पहुंची तो 21 साल की मारिया एडुआर्डा रोड्रिग्स डी फ्रीटास अभी जिंदा थी.

एक हादसा, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए

मारिया की मौत ने एक बार फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स में सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अगर सुरक्षा रस्सी सही तरीके से लगाई गई होती, तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था. लेकिन इस पूरी घटना का सबसे भावुक हिस्सा वह है, जब 130 फीट नीचे गिरने के बाद भी मारिया कुछ देर तक जिंदा थी और एक नर्स उसे हिम्मत बंधा रही थी.

ऊंट पर बैठकर ऑफिस का काम करता दिखा शख्स

क्या आपने कभी किसी को ऊंट की पीठ पर बैठकर ऑफिस का काम करते देखा है? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों को हैरान भी किया है और हंसने पर भी मजबूर कर दिया है. वीडियो में एक शख्स सहारा रेगिस्तान के बीच ऊंट की पीठ पर बैठा लैपटॉप पर काम करता नजर आ रहा है. इसे देखकर इंटरनेट यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. न्यूयॉर्क के कंटेंट क्रिएटर साद अख्तर ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

प्रिंटेड मोनोकनी में तस्वीरें शेयर कर ढाया कहर

किश्वर मर्चेंट का बीच पर दिखा किलर लुक

टीवी एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट बीते कई दिनों से पति और बेटे संग वेकेशन पर हैं. किश्वर लगातार वेकेशन की तस्वीरें शेयर करके फैंस को ट्रीट दे रही हैं. किश्वर ने अब Beach से अपनी किलर तस्वीरें शेयर की हैं. प्रिंटेड मोनोकनी में वो कहर ढाती दिखीं. मोनोकनी संग एक्ट्रेस ने ग्लोइंग मेकअप किया. ब्लैक सनग्लासेस और सटल मेकअप में किश्वर ने खूब टशन दिखाया. बीच पर जमीन पर बैठकर रेत में लिपटते हुए 45 साल की हसीना

ने किलर पोज भी दिए. किश्वर के एक्सप्रेशन्स, अदाएं और स्वैग देखते ही बनता है.

अक्षय कुमार ने उड़ाए फराह खान के पैसे!

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार अपनी फिटनेस, अनुशासन और समय की पाबंदी के लिए जाने जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब वो फिल्म की शूटिंग पर रोज हेलीकॉप्टर से पहुंचा करते थे? ये खुलासा खुद एक्टर अक्षय कुमार और फिल्ममेकर फराह खान ने किया है. हाल ही में फराह खान, अक्षय कुमार, प्रियदर्शन

और राजपाल यादव फिल्म 'भूत बंगला' के प्रमोशन के दौरान साथ बैठे थे. इस दौरान फराह और अक्षय ने साल 2010 में आई फिल्म 'तीस मार खान' की शूटिंग से जुड़ा एक मजेदार किस्सा शेयर किया.

राम भक्तों की आस्था को पहुँची ठेस

नई दिल्ली। अयोध्या में रामलला मंदिर चढ़ावा चोरी होने की घटना पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने कड़ा बयान जारी किया। संघ ने कहा कि यह घटना केवल चोरी का मामला नहीं है, बल्कि इससे करोड़ों राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा को गहरा आघात पहुंचा है। संघ ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए मंदिर प्रबंधन और व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष, करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यही कारण है कि यह मंदिर पूरे हिंदू समाज की आस्था, श्रद्धा और भक्ति का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में अयोध्या स्थित श्री रामलला मंदिर के दान पात्रों में जमा धनराशि की चोरी की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संघ ने कहा कि इस घटना से पूरे समाज और राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए इस मामले को सामान्य अपराध की तरह नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े गंभीर विषय के रूप में देखा जाना चाहिए। संघ ने अपने बयान में कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। जांच दल की सिफारिश के आधार पर कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संघ ने स्पष्ट कहा कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि न्याय तभी पूरा माना जाएगा, जब दोषियों को कानून के अनुसार सख्त दंड मिलेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि इस घटना को असाधारण मानते हुए मंदिर प्रबंधन को व्यवस्था और संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। संघ के अनुसार वर्तमान में जो भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी है, उसे जल्द समाप्त करना जरूरी है। इसके लिए मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल आवश्यक पहल करें। संघ ने विश्वास जताया कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन, पूरी पारदर्शिता, मजबूत निगरानी व्यवस्था और धार्मिक पवित्रता के वातावरण के जरिए श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास और अधिक मजबूत करेगा।

साजिश को विफल करना समाज की जिम्मेदारी

संघ ने कहा कि इस कठिन समय में समाज को भावनाओं में बहने के बजाय जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी शक्तियां हिंदू धर्म तथा समाज को बदनाम करने का प्रयास कर सकती हैं। ऐसे किसी भी षड़यंत्र को विफल करना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। संघ ने भरोसा जताया कि निष्पक्ष जांच, पारदर्शी व्यवस्था और प्रभावी सुधारों के जरिए मंदिर की गरिमा, पवित्रता और करोड़ों राम भक्तों की आस्था पहले की तरह अटूट बनी रहेगी।

एसआईटी ने की 33 लोगों से 3 घंटे पूछताछ

अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने शुक्रवार को जांच का दायरा और बढ़ा दिया. जांच के तहत दानदाताओं, भूमि खरीद से जुड़े लोगों, प्रॉपर्टी डीलरों, बैंक कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों समेत कुल 33 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया. सभी से करीब तीन घंटे तक अलग-अलग बिंदुओं पर पूछताछ की गई. सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने ट्रस्ट की तरफ से की गई भूमि खरीद से जुड़े दस्तावेजों की भी गहन पड़ताल शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन, मकान, भुगतान प्रक्रिया और उससे जुड़े अभिलेखों के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई गई. जांच टीम यह भी समझने का प्रयास कर रही है कि भूमि खरीद की पूरी प्रक्रिया किस तरह पूरी की गई थी. जांच के दौरान कुछ प्रॉपर्टी डीलरों से भी पूछताछ की गई. इसके अलावा टिन्नू यादव के दो भांजों को भी एसआईटी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया. दोनों प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं. जांच एजेंसी ने उनसे भी जमीन से जुड़े लेनदेन और अन्य पहलुओं पर जानकारी ली।

भाजपा ने आस्था और श्रद्धा के साथ किया खिलवाड़

अयोध्या में आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया

स्वतंत्र भारत ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने अयोध्या में आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया है। अयोध्या प्रभु श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात गांव-गांव और घर-घर पहुंच गयी है। अब भाजपा को न चंदा मिलेगा न दान और न वोट मिलेगा। भाजपा ने मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्रीराम और देश के संविधान दोनों के साथ दगा किया। प्रभु श्रीराम इन्हें माफ नहीं करेंगे। गुरूवार को समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय, लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि मर्यादा पुरषोत्तम श्रीराम के चढ़ावे के बारे में जनता ने अगर सही बता दिया तो यह मामला जितना दिख रहा है, उससे बहुत बड़ा होगा। अभी तो गुप्त दान का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का जो काम है, समाजवादी पार्टी वही जिम्मेदारी निभा रही है। भाजपा सरकार ने अयोध्या में एयरपोर्ट और अन्य जगहों पर जमीन के मुआवजे में भेदभाव किया। उनके साथ अन्याय किया। उन्हें प्रताड़ित किया। वहां के लोगों ने सरयू नदी में खड़े होकर भाजपा को वोट नहीं देने की कसम खायी थी। इसी तरह से अयोध्या में सड़कों के चौड़ीकरण में व्यापारियों और आम लोगों के मकानों दुकानों का उचित मुआवजा नहीं मिला। जमीनों के साथ बड़े पैमाने पर हेरफेर हुआ। भाजपा सरकार ने अयोध्या के लोगों के साथ न्याय नहीं किया। अयोध्या के पंच प्रमुख मंदिर राम निवास धाम के मामले में अखिलेश यादव ने कहा कि मंदिर के हरिशंकर सफारी वाला की बात और उनकी मांगों की चर्चा भी राममंदिर के चढ़ावा चोरी की तरह होगी, इन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। थानों को भाजपा के लोग चला रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश की जनता ने कभी नहीं देखा। भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस का दावा जीरो है। पुलिस की स्थिति तो यह है कि हथेली गरम, पुलिस नरम। उत्तर प्रदेश में हर विभाग में सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार चल रहा है। थाना और पुलिस भाजपा के इशारे पर काम कर रहे है इसीलिए लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। एक्सप्रेस-वे की सड़कों में हो रहे गड्ढे और अन्य कमियों पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार क्वालिटी से कम्प्रोमाइज करती है। भाजपा का हर काम और हर योजना भ्रष्टाचार के लिए बनायी जाती है। देहरादून-दिल्ली हाई-वे तो ताजा उदाहरण है। इसे पहले प्रधानमंत्री ने जब बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया था तभी उसमें गड्ढे हो गये थे। कई जगह उखड़ गया। गंगा-एक्सप्रेस-वे में काफी कमियां देखने को मिल रही है। किसानों के खाद संकट के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि यूरिया, डीएपी उर्वरक का संकट है। सरकार की पहले से कोई तैयारी नहीं है। डीएपी खाद नहीं मिल रही है। आने वाली फसल गेहूं, आलू आदि के लिए और संकट आएगा। उन्होंने कहा कि हर फसल का कैलेण्डर होता है अगर समय पर खाद-बीज, पानी नहीं मिल पाया तो किसानों को भारी नुकसान होता है। इससे पहले प्रेस कांफ्रेंस में अयोध्या के पंच प्रमुख मंदिर राम निवास धाम के हरिशंकर सफरीवाला ने चंपत राय बंसल पर उनके 1987 के पंजीकृत मंदिर को हड़पने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मंदिर के पुजारी को बरगला कर बैनामा बिना कब्जा कर मंदिर का दान, मूर्तियां, पलंग, सिंहासन आदि हड़प लिया। मंदिर समिति को बिना जानकारी दिए 5 करोड़ 80 लाख में पुजारी से सौदा कर लिया। पुजारी को 60 लाख अग्रिम देकर कब्जा कर लिया।

ए.आई. कैमरों से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर सतत दृष्टि

शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET-2026) की लिखित परीक्षा तीन दिन 02, 03 व 04 जुलाई 2026 को आयोजित की जा रही है। गुरुवार को पहले दिन प्रथम पाली पूर्वाह्न 09:30 बजे से 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपरान्ह 02:30 बजे से 05:00 बजे तक प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक, पारदर्शी एवं नकलविहीन वातावरण में संपन्न हुई।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रुम से उनकी, सदस्यगण, सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं उपसचिव की उपस्थिति में सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। ए.आई. कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर सतत दृष्टि रखी गई। एआई की मदद से संदिग्धों की जाँच के पश्चात प्रथम पाली में 07 एवं द्वितीय पाली में 08 फर्जी परीक्षार्थी, जो दूसरे परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे, पकड़े गए। इनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु उन्हें स्थानीय पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सभी केंद्रों पर परीक्षा सुचारु, शुचितापूर्ण एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई।

हलाला और तीन तलाक जैसे रस्म-रिवाज कानूनन अपराध

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निकाह, हलाला और तीन तलाक जैसे रस्म -रिवाजों के चक्रव्यूह में फंसा कर महिला के यौन शोषण की

■ कोर्ट ने इन्हें 'चक्रव्यूह' की संज्ञा दी

इजाजत नहीं दी जा सकती। यह हमारे समाज का वह काला पत्रा है, जो संवैधानिक मूल्यों, समानता और मानवीय गरिमा की अवधारणा से कोसों दूर है। ये कृत्य न केवल कानूनन अपराध हैं, बल्कि ये समाज की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोरने वाले हैं। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने पीड़िता के पूर्व पति, चाचा, मौलाना समेत अन्य रिश्तेदारों की याचिका खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों की आड़ में अपराधों का संरक्षण नहीं किया जा सकता। प्रथम दृष्टया यह मामला नाबालिग संग सोची समझी रणनीति के साथ सामूहिक दुष्कर्म का है। इसकी गहन जांच जरूरी है।

मामला अमरोहा के सैदनागली थाना क्षेत्र का है। एफआईआर के मुताबिक पीड़िता का निकाह 2015 में तब हुआ था जब वह महज 15 वर्ष की थी। इसके बाद तीन तलाक, फिर निकाह हलाला और पुनः निकाह के चक्रव्यूह में फंसाकर उसका लगातार यौन शोषण किया गया। पीड़िता का आरोप है कि 19 फरवरी 2025 को फिर से निकाह का झांसा देकर उसे हलाला के नाम पर दरिंदगी का शिकार बनाया गया। व्यक्तिगत कानूनों और धार्मिक प्रथाओं का हवाला देते हुए आरोपियों ने अलग-अलग चार याचिकाएं दाखिल कर मुकदमा रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। लेकिन कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियों संग याचिका खारिज कर दी।

आदेश के अंत में कोर्ट ने कहा कि अब तक जो भी तथ्य सामने आए हैं, वे अंतरात्मा को झकझोर देने वाले हैं। यहां सभी आरोपियों ने ऐसे गिरोह के रूप में जो भूमिका निभाई, वह प्रथम दृष्टया देश के कानूनों के खिलाफ है। कुछ की भूमिका सहायक या षड्यंत्रकारी के रूप में हो सकती है, लेकिन विवेचना के इस प्रारंभिक स्तर पर उन्हें एफआईआर रद्द कराने की मांग करने का हक नहीं है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार आज भी राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा : गोविंद नारायण शुक्ल

मौरावां में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन, राष्ट्रवाद और संगठन की मजबूती पर दिया गया जोर

स्वतंत्र भारत (ब्यूरो) उन्नाव। भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई के तत्वावधान में गुरुवार को पुरवा विधानसभा क्षेत्र के मौरावां स्थित भाजपा कार्यालय में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती संस्मरण पखवाड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों, उनके राजनीतिक योगदान और संगठन की मजबूती पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) गोविंद नारायण शुक्ल, पुरवा विधायक अनिल सिंह, अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री संजय गुप्ता, क्षेत्रीय मंत्री दिलीप यादव तथा भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद नेताओं ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम् के सामूहिक गायन से हुई।

मुख्य अतिथि गोविंद नारायण शुक्ल ने कहा कि स्वतंत्र भारत के शुरुआती दौर में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के औद्योगिक विकास की मजबूत नींव रखी। उन्होंने चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री और सिंदरी उर्वरक कारखाने जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए उनका संघर्ष और बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। धारा 370 हटना उनके संकल्प को सच्ची श्रद्धांजलि है।

पुरवा विधायक अनिल सिंह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का राष्ट्रवाद और अखंड भारत का सपना आज भी भाजपा की कार्यशैली का आधार है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ समाज और क्षेत्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। क्षेत्रीय मंत्री संजय गुप्ता और दिलीप यादव ने संगठन को मजबूत बनाने में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए पार्टी की नीतियों और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। अध्यक्षीय संबोधन में भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूरा जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित रहा। उनका एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं चलेंगे का उद्घोष अखंड भारत के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री रजनीश वर्मा ने किया। सम्मेलन में जिला उपाध्यक्ष नवीन सिंह, मनोज सिंह, जिला मंत्री अवनीश शुक्ला, जिला मीडिया प्रभारी समीर शुक्ल, जिला कार्यसमिति सदस्य संजय त्रिपाठी, वरिष्ठ भाजपा नेता गणेश शंकर मिश्र, आदित्य जायसवाल, जय सिंह कुशवाहा, महेश रावत, अजय बाजपेई, शुभम श्रीवास्तव, मौरावां मंडल अध्यक्ष रामशंकर राजपूत सहित विभिन्न मंडलों के पदाधिकारी, ब्लॉक प्रमुख एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

मंत्री के निरीक्षण में गौशाला की खुली पोल, अव्यवस्थाओं पर जिम्मेदारों को लगाई फटकार

स्वतंत्र भारत (ब्यूरो) उन्नाव। प्रदेश के पशुधन मंत्री कृष्णा पासवान के थाना गांव स्थित वृहद गौशाला के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की वास्तविक तस्वीर सामने आ गई। निरीक्षण के समय गौशाला के संचालन और गोवंश की देखरेख में कई गंभीर खामियां उजागर हुईं, जिस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार के निर्देश दिए।

बताया जाता है कि जिस गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) के माध्यम से गौशाला का संचालन किया जा रहा है, उसके कार्यों पर निरीक्षण के दौरान कई सवाल खड़े हुए। मंत्री के सामने एक के बाद एक कमियां सामने आती रहीं, जिससे मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान पशुधन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौशालाओं में गोवंश के चारा, पानी, उपचार और साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गोवंश की देखभाल में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जांच में दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

वन महोत्सव सप्ताह का शुभारंभ, 'एक वृक्ष मां के नाम' अभियान के तहत हुआ पौधरोपण

वन विभाग ने आयोजित किया 'आम वृक्ष भंडारा', ग्रामीणों को वितरित किए फलदार पौधे

स्वतंत्र भारत (ब्यूरो) बांगरमऊ उन्नाव। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा वन महोत्सव सप्ताह का शुभारंभ ग्राम डडिया सुनौरा स्थित पंचायत भवन परिसर में किया गया। कार्यक्रम के दौरान 'एक वृक्ष मां के नाम' अभियान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया गया। साथ ही 'आम वृक्ष भंडारा' आयोजित कर ग्रामीणों और राहगीरों को फलदार पौधे वितरित किए गए, जिससे अधिक से अधिक लोग वृक्षारोपण के लिए प्रेरित हो सकें।

कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान महेंद्र कुमार ने की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। यदि हर व्यक्ति एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प ले, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा।

इस अवसर पर ग्राम प्रधान, वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया। उपस्थित लोगों ने रोपे गए पौधों की सुरक्षा और नियमित देखभाल का संकल्प लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

वन महोत्सव के तहत आयोजित 'आम वृक्ष भंडारा' में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और राहगीरों को आम सहित अन्य फलदार पौधों का वितरण किया गया। अधिकारियों ने लोगों से अपने घरों, खेतों और सार्वजनिक स्थलों पर अधिक से अधिक पौधे लगाने और उन्हें वृक्ष बनने तक संरक्षित रखने की अपील की।

क्षेत्रीय वन अधिकारी नीरज कुमार विद्यार्थी ने कहा कि वृक्ष मानव जीवन का आधार हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, जल संरक्षण, शुद्ध वायु और जैव विविधता के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी से वन महोत्सव को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया।कार्यक्रम में वन दरोगा अवधेश कुमार अवस्थी, पप्पू सिंह यादव, ऋषभ सिंह, वन रक्षक राजकुमार, विपिन कुमार सहित वन विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण एवं गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया।

आईजीआरएस रैंकिंग में उन्नाव ने लगाई लंबी छलांग, प्रदेश में चैथा स्थानय बांगरमऊ तहसील बनी नंबर-1

राजस्व शिकायतों के निस्तारण में उत्कृष्ट प्रदर्शन, डीएम ने अधिकारियों की सराहना कर दी बेहतर रैंकिंग बनाए रखने की नसीहत

स्वतंत्र भारत (ब्यूरो) उन्नाव। राजस्व शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में उन्नाव जनपद ने प्रदेश स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जून-2026 की आईजीआरएस (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) मूल्यांकन रिपोर्ट में उन्नाव को प्रदेश में चैथा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं तहसीलवार रैंकिंग में बांगरमऊ तहसील ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर जनपद का गौरव बढ़ाया है।

रिपोर्ट के अनुसार तहसील पुरवा को प्रदेश में 11वीं तथा सफीपुर तहसील को 27वीं रैंक प्राप्त हुई है। पिछले माह उन्नाव जनपद प्रदेश में 10वें स्थान पर था, जबकि जून माह की रैंकिंग में छह स्थान की छलांग लगाकर चैथे स्थान पर पहुंच गया है। प्रशासन इसे जिलाधिकारी घनश्याम मीना की नियमित मॉनिटरिंग और प्रभावी समीक्षा का परिणाम मान रहा है।जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने बताया कि राजस्व कार्यों की प्रगति की वह प्रतिदिन सभी उपजिलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा करते हैं। शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण, सतत निगरानी और जवाबदेही के कारण जनपद की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

उत्कृष्ट प्रदर्शन पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी बांगरमऊ, उपजिलाधिकारी पुरवा, उपजिलाधिकारी सफीपुर तथा उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि बांगरमऊ तहसील ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन किया है, जबकि पुरवा और सफीपुर का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य तहसीलों के अधिकारी भी इससे प्रेरणा लेकर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें और जनपद की सभी तहसीलों को प्रदेश की शीर्ष 10 रैंकिंग में लाने का लक्ष्य निर्धारित करें।

ऑनलाइन समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रतिदिन संबंधित अधिकारियों के साथ राजस्व कार्यों की समीक्षा करें, शिकायतों के निस्तारण की सघन निगरानी रखें और गुणवत्ता से कोई समझौता न करें। उन्होंने कहा कि पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी कार्यप्रणाली से ही जनपद की बेहतर रैंकिंग को बरकरार रखा जा सकता है। ऑनलाइन समीक्षा बैठक में जनपद के सभी उपजिलाधिकारी मौजूद रहे।

धूमधाम से मनाया गया सदगुरु कबीर साहेब का प्रगट दिवस

शोभायात्रा, सत्संग, भजन-कीर्तन और विशाल भंडारे में उमड़े हजारों श्रद्धालु

स्वतंत्र भारत (ब्यूरो) उन्नाव। ग्राम फत्तेपुर स्थित सदगुरु कबीर मंदिर ज्ञान वाटिका आश्रम में सदगुरु कबीर साहेब का प्रगट दिवस श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। सुबह से शुरू हुए धार्मिक कार्यक्रम देर रात तक चलते रहे, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया।

कार्यक्रम की शुरुआत भव्य शोभायात्रा से हुई। शोभायात्रा में कबीर साहेब की वाणी और उपदेशों के माध्यम से जन-जन को उनके संदेश से अवगत कराया गया। श्रद्धालुओं ने नाच-गाकर और भजन गाते हुए कबीर साहेब के प्रगट दिवस का उत्सव मनाया।आश्रम परिसर में दिनभर मीठे जल, सब्जी-पूड़ी, खीर, बूंदी सहित विभिन्न प्रसादों का वितरण चलता रहा। श्रद्धालुओं ने इसे सदगुरु की कृपा बताते हुए उत्साहपूर्वक प्रसाद ग्रहण किया।सायंकाल महंत सुभाष चंद्र दास साहेब ने चैका, आरती और पूजन कर भक्तों को पान-परवाना वितरित किया। इसके बाद सत्संग, भजन-कीर्तन और रात्रि जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें कबीर साहेब के जीवन, उपदेश और प्राकट्य पर प्रकाश डाला गया।युवा प्रतिनिधि अरुण दास ने जीव दया, आत्म पूजा तथा कबीर मिशन के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर विस्तार से विचार रखे। उन्होंने कबीर पंथ और सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब की वंशावली की जानकारी भी श्रद्धालुओं को दी।गुरु माता अनुराधा जी ने ÷झूल रहे साहेब कबीर बन कर के लालना÷ सोहर गाकर उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रगट दिवस की शुभकामनाएं दीं। वहीं समाजसेवी डॉ. मनीष सेंगर ने कबीर साहेब की अमृतवाणी की वर्तमान समय में प्रासंगिकता बताते हुए उनके बताए मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा दी।कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही और पूरा आश्रम ÷सत साहेब÷ के जयघोष से गूंजता रहा।

गलत वरासत पर प्रशासन सख्त विवादित भूमि की खरीद-फरोख्त पर रोक

मामला उजागर होते ही तहसील प्रशासन की कार्रवाई, लेखपाल को नोटिस जारी, जांच शुरू

स्वतंत्र भारत (ब्यूरो) हसनगंज उन्नाव। मखदूमपुर गांव में एक बीघा कृषि भूमि की कथित गलत वरासत का मामला प्रकाश में आने के बाद तहसील प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद तहसीलदार अविनाश चैधरी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए विवादित भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी है। साथ ही संबंधित लेखपाल को नोटिस जारी कर पूरे प्रकरण पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

मखदूमपुर निवासी कैलाश और बेचेलाल ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के साथ जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि उनकी दादी स्वर्गीय सूखा रावत की लगभग एक बीघा कृषि भूमि की वरासत नियमों के अनुसार उनके नाम दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन क्षेत्रीय लेखपाल ने कथित रूप से गांव के शिवनाथ, बिंदा प्रसाद, अर्जुन और भीम के नाम वरासत दर्ज कर दी, जबकि उनका परिवार से कोई संबंध नहीं है। पीड़ितों के अनुसार उन्होंने 9 जून को तहसीलदार न्यायालय में वाद दाखिल कर अपने दावे के समर्थन में सभी आवश्यक अभिलेख और साक्ष्य प्रस्तुत

यूपी में लगातार सातवें साल बिजली दरें नहीं बढ़ेंगी
योगी सरकार के फैसले से उपभोक्ताओं को राहत

सरकार ने यह भी कहा है कि प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे के करीब निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने, शहरी इलाकों में ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने, जर्जर लाइनों को बदलने और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए लगातार सातवें वर्ष बिजली दरों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2026-27 के लिए मौजूदा बिजली टैरिफ ही प्रभावी रहेगा। इस फैसले का लाभ घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि और अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलेगा। सरकार का कहना है कि महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत को देखते हुए आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं होगा, इसलिए बिजली दरों को यथावत रखने का फैसला लिया गया है।ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार बिजली वितरण कंपनियों की ओर से टैरिफ संशोधन का प्रस्ताव नियामक आयोग के समक्ष रखा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं के हित को प्राथमिकता देते हुए बिजली दरें नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया। सरकार का मानना है कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन, बिजली चोरी पर प्रभावी नियंत्रण, तकनीकी एवं वाणिज्यिक नुकसान में कमी तथा बिल वसूली की व्यवस्था को मजबूत कर वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डाले बिना बिजली क्षेत्र को मजबूत बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा।सरकार ने यह भी कहा है कि प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे के करीब निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने, शहरी इलाकों में ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने, जर्जर लाइनों को बदलने और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ऊर्जा विभाग का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसका लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है।बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं किए जाने के फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए जनता को राहत देने का प्रयास कर रही है। उनका आरोप है कि यह निर्णय राजनीतिक दृष्टि से लाभ हासिल करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता हमेशा जनकल्याण और सुशासन रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और बिजली क्षेत्र में हुए सुधारों के कारण ही उपभोक्ताओं को लगातार सात वर्षों तक राहत देना संभव हो पाया है।ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि बिजली दरें स्थिर रहने से घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बजट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही छोटे उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और कृषि क्षेत्र को भी आर्थिक राहत मिलेगी। हालांकि विशेषज्ञों ने यह भी सुझाव दिया है कि वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने के लिए राजस्व संग्रह में सुधार, स्मार्ट मीटरिंग, बिजली चोरी पर सख्ती और आधारभूत ढांचे में निरंतर निवेश आवश्यक होगा। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि भविष्य में भी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, निर्बाध और किफायती बिजली उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे।

युवक ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। पत्नी के मायके से वापस नहीं आने से परेशान एक युवक ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पहले उसने अपनी पत्नी को फोन कर बच्चों का ख्याल रखने और उससे बेहद प्यार करने की बात कही थी। कुछ ही देर बाद उसकी मौत की खबर ने पूरे परिवार और गांव को गहरे सदमे में डाल दिया। यह घटना ललौली थाना क्षेत्र के पथरी मजरा अढ़ावल गांव की है। पुलिस के अनुसार, 35 साल के अमित निषाद अपने घर में फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है। परिजनों ने बताया कि अमित शारीरिक रूप से दिव्यांग था और मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। उसकी पत्नी अनीता इन दिनों अपने मायके में एक शादी समारोह में शामिल होने गई हुई थी। अमित लगातार उसे घर लौटने के लिए कह रहा था, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आई थी। बताया जा रहा है कि घटना से पहले अमित ने पत्नी को फोन किया। दोनों के बीच करीब पांच मिनट तक बातचीत हुई। परिजनों के मुताबिक, फोन पर उसने कहा कि अब तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इसके बाद उसने घर के अंदर साड़ी के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब काफी देर तक अमित बाहर नहीं आया तो परिजनों ने कमरे में जाकर देखा। वहां वह फंदे से लटका मिला। यह नजारा देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए।

पूछताछ के दौरान अनिल मिश्रा ने टिन्नू यादव पर आरोप लगाए

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। विशेष जांच दल (एसआईटी) अब केवल चोरी के आरोपों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि पिछले पांच वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट और निर्माण कार्यों की भी गहन जांच करने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, शुरुआती पड़ताल में कई ऐसे संकेत मिले हैं जो बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी को अब तक मिले कुछ अहम साक्ष्यों के आधार पर ट्रस्ट से जुड़े प्रमुख पदाधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। इनमें ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा, निर्माण कार्यों से जुड़े गोपाल राव और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नाम भी चर्चा में हैं। जांच एजेंसी ने मंदिर ट्रस्ट द्वारा पिछले पांच वर्षों में कराए गए ऑडिट की स्वतंत्र समीक्षा करने का फैसला लिया है। इस प्रक्रिया में ऑडिट रिपोर्टों में संभावित खामियों, वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था की पड़ताल की जाएगी। सूत्रों का दावा है कि प्रारंभिक जांच में कई ऐसे बिंदु सामने आए हैं, जिनकी विस्तृत जांच से और परतें खुल सकती हैं। इसी सिलसिले में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक (रेंज) किरण एस और विशेष वित्त सचिव नील रतन की बैठक प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद जांच की आगामी रणनीति तय की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, एसआईटी की पूछताछ के दौरान डॉ. अनिल मिश्रा ने कथित तौर पर गणनाकर्मी टिन्नू यादव को पूरे मामले का प्रमुख जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि चढ़ावे की गणना में लगे अधिकांश कर्मचारी टिन्नू यादव के निर्देशों पर काम करते थे। वहीं, अनिल मिश्रा ने अपनी किसी प्रत्यक्ष भूमिका से इनकार किया है। हालांकि जांच अधिकारियों ने उनसे यह भी पूछा कि मंदिर प्रबंधन में प्रभावशाली भूमिका होने के बावजूद करोड़ों रुपये की कथित हेराफेरी की जानकारी उन्हें कैसे नहीं मिली। इस पर उन्होंने कहा कि चोरी का मामला स्वयं ट्रस्ट की ओर से सामने लाया गया और संदेह होने पर जांच शुरू कराई गई। उन्होंने निगरानी व्यवस्था में चूक स्वीकार की, लेकिन कई महत्वपूर्ण सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

100 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन से जुड़े कथित घोटाले की जांच निर्णायक चरण में

उत्तर प्रदेश के संभल में करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 38 बीघा सरकारी और ग्राम सभा की जमीन से जुड़े बहुचर्चित भूमि घोटाले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। तत्कालीन अधिशासी अधिकारी (ईओ) राजकुमार गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का दावा है कि यह केवल अवैध कब्जे का मामला नहीं, बल्कि फर्जी पट्टा तैयार करने, सरकारी अभिलेखों में नामांतरण कराने, हाईकोर्ट में चल रही कानूनी लड़ाई खत्म कराने और सरकारी जमीन को निजी हाथों में पहुंचाने की कथित सुनियोजित साजिश थी। अब पूरे नेटवर्क में शामिल लोगों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है। पुलिस जांच के अनुसार, संभल-मुरादाबाद हाईवे स्थित ग्राम तख्तगुशाईन की करीब 2.367 हेक्टेयर (लगभग 38 बीघा) ग्राम सभा और नगर पालिका की जमीन इस पूरे मामले का केंद्र है। आरोप है कि 12 जुलाई 1967 का एक कथित फर्जी पट्टा तैयार किया गया और उसी के आधार पर 15 फरवरी 2008 को तत्कालीन उप संचालक चकबंदी से सईदुल रहमान के पक्ष में नामांतरण करा लिया गया। इसके बाद सरकारी जमीन पर कब्जे का रास्ता साफ हो गया। नगर पालिका ने नामांतरण आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वर्ष 2013 में तत्कालीन ईओ राजकुमार गुप्ता द्वारा याचिका वापस लेने के बाद सरकारी पक्ष की कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई।